

Kind attention: Cdr S. Bhattacharya
To 01912700000



एन.टी.पी.सी. लिमिटेड

(मान सम्मान के साथ)

NTPC Limited

(A Govt. India Enterprise)

श्रीलक्ष्मी नदी परियोजना
Sri Laxmi Nadi Project

Ref.No.NTPC-Sipat/HR/SP/School/

Dt.26.07.06

To

The Secretary,
Central Board of Secondary Education,
New Delhi

Dear Sir,

Introducing ourselves as the premier Power utility of the country under the ministry of energy, Govt. of India this is to submit for your kind information that we are constructing a Super Thermal Power Project at Sipat, Bilaspur(Chhatisgarh). In its ultimate stage, the power station would have an employee strength of 1212, a CISF strength of 300, a sizeable number of associates besides the local population of the neighborhood villages.

In line with our welfare policy envisaging provision of schools in our township, we have started a Bai Bhasani Public School in association with the Child Education Society, New Delhi on 03.07.06 having classes from LKG to Class VII to cater to the educational needs of the children of our employees and other stakeholders.

With a view to getting our school registered with CBSE, we are making this on line application enclosing the following documents in fulfillment thereof.

1. Copy of Registration letter of the Trust/Society Management Committee.
2. Land Certificate from concerned authority(as per enclosed proforma)(Extent of land of the school complex measures 11 acres).
3. Affidavit of(Non-proprietary Character of Society).

Requesting an early action in the matter and thanking you in anticipation.

Thanking you,

Yours sincerely,


(S. Phola)
Sr.Manager(HR)


Shashi Nigam
Principal
Bai Bhasani Public School
NTPC, Sipat, Bilaspur(Ct)


Chairman/Secretary
For Authorised Signatory
BBPS Caution Moeny Account

छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग
मंत्रालय, रायपुर

क्रमांक /एफ -4 - 120/सात -1/2004/राजस्व

रायपुर, दिनांक 3//2004

प्रति,

कलेक्टर
जिला-बिलासपुर
(उ.प.)

विषय : नेशनल धर्मल पावर कार्पोरेशन सीपत को टाउनशिप निर्माण हेतु ग्राम सीपत स्थित शासकीय भूमि के आबंधन बाबत

संदर्भ : आपका पत्र क्रमांक 2375/भू-बंधन/2004 दिनांक 16.04.04 एवं पत्र क्रमांक 7626/भू-बंधन/2004 दिनांक 6.11.04

राज्य शासन एतद् द्वारा नेशनल धर्मल पावर कार्पोरेशन सीपत को टाउनशिप निर्माण हेतु ग्राम सीपत ही परवारी हल्का नं. 28 तहसील मल्लूरी जिला -बिलासपुर स्थित शासकीय भूमि खसरा नं. 954 में से रकबा 9.40 एकड़ , कुल योग 9.40 एकड़ भूमि वर्ष 2004-2005 की गार्ड सार्इन अनुसार ग्रन्थ्याजी राशि रुपये 20,92,200.00 (बीस लाख ब्यान्वे हजार दोसौ रुपये मात्र) एवं वार्षिक भू-भाटक 1,56,915.00 (एक लाख छप्पन हजार नौसी पंद्रह रुपये मात्र) लेकर राजस्व पुस्तक परिपत्र भाग -1 खण्ड-07 के अनुसार स्थायी पट्टे पर आबंधन की स्वीकृति सामान्य शर्तों के साथ-साथ निम्न विशेष शर्तों पर प्रदान करता है :-

1. यह कि यदि दी गई भूमि उस विशिष्ट प्रयोजना या प्रयोजनों को छोड़ जिसके/ जिनके लिये दी गई हो, किसी अन्य प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाई जाये तो शासन उसे वापस ले लेगा।
2. यह कि यदि दी गई भूमि किसी भी समय राज्य शासन द्वारा वापस ले ली जाये तो उसके मुआवजे की रकम भूमि प्राप्त करने के लिये शासन को भुगतान की गई (यदि कोई हो) और साथ ही भूमि ग्रहिता द्वारा भूमि की लागत या उनके वर्तमान मूल्य जो भी कम हो से अधिक नहीं होगी।
3. यह कि भूमि ग्रहिता की ओर से शर्तों के भंग किये जाने के परिणाम स्वरुप शासन द्वारा भूमि वापस ले ली जाये तो शासन निम्नलिखित दो बातों में से कोई भी कर सकता है :-

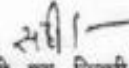




- (क) भूमि पर निर्मित की गई किन्हीं इमारतों को उनकी लागत अथवा वर्तमान मूल्य जो भी कम हो का भुगतान कर अपने अधिकार में लेना अथवा ,
- (ख) भूमि ग्रहिता से यह कहना की यह इमारतों को हटा दे और शासन द्वारा नियत उचित अथधि में उसकी मूल स्थिति में ला दे यदि भूमि ग्रहिता इस आदेश का पालन नहीं करेगी तो इमारत अथवा इमारतें शासन के कब्जे में चली जायेगी ।
- (2) आदेश जारी होने की तिथि से आवेदक/संस्था से प्रख्याजि की संपूर्ण राशि तथा वार्षिक भू - भाटक की राशि 6 माह के अन्दर जमा कराये यदि वे निर्धारित अथधि तक प्रख्याजि व भू - भाटक राशि जमा नहीं करते हैं तो आवंटन आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा ।

संलग्न :- मूलतः रा. प्र. क. - /अ - 19 (3) / 2002 - 2003 ग्राम सीपत ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

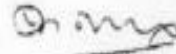

(पी. एस. तिथारी)
अवर सचिव


छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक / फ - 4 - 120 / सात - 1 / 2004 / राजस्व
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 31 DEC 2004

- (1) निज सचिव माननीय मंत्री जी राजस्व
(2) महाप्रबंधक, एन. टी. पी. सी. सीपत, जिला बिलासपुर की ओर सूचनायं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।


31/12
अवर सचिव


छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग
31/12

* The plots highlighted is the land on which
the school complex has been developed (i)

कार्यालय कलेक्टर, बिलासपुर [मोडो]

[जिला योजना समिति]

-जादेश-

राजपू/11-अ-19/99-2000

क्रमांक/ 42 / ज. यो. स. मू-अंटेन/2000 बिलासपुर, दिनांक: 30 मार्च, 2000

जिला योजना समिति के निर्णय दिनांक 18.3.2000 के अनुसार

नेशनल धर्मत पावर कारपोरेशन [एन. टी. पी. सी.] सीपत-बिलासपुर को ग्राम सीपत
तहसील मस्तुरी स्थित भूमि खसरा नं. 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814/1

814/2, 815/1, 815/2, 816, 817/1, 817/2, 818, 819, 820, 821,

822, 823, 824, 825, 826, 827, 831, 832, 841, 842, 843/1, 844,

849, 853, 860, 861, 862/1, 862/2, 864/1ख, 949/2, 951/2, 952/2,
953/2, 957/2, 862/3, 863/1, 863/3, 864/1ख, 964/1ग, 873, 880,

882/1, 885/1, 891, 893, 894, 928/1क, 928/1ख, 928/1ग, 928/4,

928/7, 939, 949/1, 950, 951/1, 951/3, 952/1, 952/3, 953/1,

953/3, 954 में से, 955, 956, 957/1, 957/3-[म. नं. 3], 559/1 में से

973/1 में से, 978/1क, में से, 981/2, 981/7, 984 में से, 982/1क, 982/1ग,

982/1घ, 991, 992/1, 993, 994/1, 994/3, 995/1, 997/1, 998/1क,

998/1ख, 1158/1, 1221/1 कुल खसरा नं. 92 रकबा कुमाः 2.60, 0.48,

0.51, 0.80, 0.57, 0.87, 0.20, 0.31, 0.27, 0.08, 0.41, 0.83,

0.11, 0.52, 0.69, 0.55, 0.56, 0.49, 1.27, 0.57, 0.79, 0.74,

1.20, 1.13, 0.83, 0.75, 0.25, 36.15, 2.00, 1.45, 2.71, 22.47,

1.80, 25.34, 20.54, 6.00, 35.45, 8.99, 23.42, 5.49, 0.42, 0.10

2.80, 16.88, 0.17, 0.58, 2.86, 101.22, 0.20, 0.17, 0.20, 0.50

2.35, 0.70, 29.74, 17.63, 4.30, 22.52, 4.80, 11.87, 7.50, 32.03

15.69, 1.20, 114.25, 4.50, 2.54, 6.00, 9.83, 1.00, 11.05, 0.24

0.10, 3.02, 1.19, 3.76, 2.05, 1.00, 1.77, 5.20, 8.30, 0.17,

3.49, 11.94 कुल रकबा 678.02 एकड़ भूमि का आंटेन मोडो-राजस्व विभाग

मंत्रालय, मोडाल के जादेश क्रमांक- एक-6-52/सात/नवम्बर/99 दिनांक 30-3-99 के

678.02

[Signature]

* अनुसार प्रख्याति रुपये 4, 55, 80, 573=00 रुपये वार करोड पचपन लाख अस्ती ह्यार पांच सौ तिहत्तर मात्र। एवं 7.5 प्रतिशत की दर से वार्षिक भू-भाटक रुपये 34, 18, 543=00 रुपये चौतीस लाख अठारह हजार पांच सौ तिरास मात्र। तैकर निम्न विशेष शर्तों के साथ इन शर्तों पर विद्युत संप्रदा की स्थापना हेतु आर्बाटित की जाती है कि संबंधित विभागों, स्थानीय निकायों, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जिन शर्तों के अधीन अपनी अनापत्ति दी है, उनका पालन करना होगा तथा प्रनाधीन भूमि पर छोड़े पैड़ु पाँचे अथवा अन्य संपत्ति निर्मित हो तो उसका मूल्यांकन कर पृथक से कलू किया जावे। आवेदित भूमि में से खनन 954 में से 9.40 एकड़ भूमि छोड़े उत्खनन कार्य हेतु मार्डनिंग लीज पर दी गई है, अतः इसे आर्बाटित नहीं किया गया है।

§1§ भूमि उपयोग अन्य उपयोग के लिए नहीं होगा अन्यथा अनाधिकृत कब्जेदार मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जावेगी या भूमि का पूर्ण बाजार मूल्य देय पैनाल्टी आदि के साथ लिया जावेगा।

§2§ भूमि या उसके किसी भाग या उस पर बने किसी भी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा और न ही किराये पर दिया जावेगा न ही विक्रय किया जावेगा या किसी अन्य प्रकार से किसी अन्य उपयोग के लिए दिया/उपलब्ध कराया जावेगा।

§3§ यदि कभी भी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिए नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों एवं संपत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और आर्बाटित को उसका मुआब्जा देय नहीं होगा।

§4§ भूमि के किसी भी उपयोग या इस पर किसी भी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियाँ/ अनुमोदन एवं अनापत्तियाँ संबंधित स्थानीय संस्थाओं, नगर निगम, नगर तथा ग्राम निका आदि से लेनी होंगी तथा मास्टर प्लान व पर्यावरण संरक्षण अधि आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा।

§5§ वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अनुमति में दी गई शर्तों तथा दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।

§6§ आवेदित भूमि जिनका उपयोग नहर, नाली, तालाब अथवा अन्य किसी रूप में सार्वजनिक रूप से किया जा रहा है, की वैकल्पिक व्यवस्था होने तक इन्हें आर्बाटित नहीं माना जावेगा।

Signature

§7§ शासन के प्रतिनिधि, अधिकृत व्यक्ति तथा जिला कौन्सिलर या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों को भूमि के सही उपयोग हेतु तथा शर्तों के पालन का निरीक्षण करने के लिए सभी भूमि तथा उस पर निर्मित बरिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

§8§ आदेश जारी होने की तिथि से आवेदक द्वारा प्रख्याजि व मु-भाटक 6 माह के भीतर शासकीय कौष में जमा कराया जावे। निर्धारित अवधि के भीतर राशि जमा न होने की स्थिति में तथा बसब उपरोक्त सभी शर्तों का पालन न किए जाने पर आर्बटन आदेश स्वयैव निरस्त माना जावेगा।

[Signature]

कौन्सिलर,

द्विलासपुर {म090}

पू050/422 /जि. यो. स./मु-बंटन/2000

द्विलासपुर, दिनांक: 30 मार्च, 2000

प्रस्तितिपि:-

- 1- अनुविभागीय अधिकारी (रा.) द्विलासपुर को सूचनाय एवं पालनाय।
- 2- सिनियर मैनेजर कंस्ट्रक्शन, नेशनल धर्मत पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (एन. टी. पी. सी. सीपत-द्विलासपुर को सूचनाय एवं पालनाय।
- 3- जिला योजना अधिकारी, जिला सरकार प्रकोष्ठ द्विलासपुर को जिला योजना समिति के निर्णय दिनांक 18.3.2000 के संदर्भ में सूचनाय।

[Signature]

कौन्सिलर,

द्विलासपुर {म0 90}

[Signature]

